डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बना एक मिसाल

–बालेन्दु शर्मा दाधीच

डिजिटल इंडिया एक विशाल अभियान के रूप में आगे बढ़ रहा है। यह देश को डिजिटलीकृत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का महत्वाकांक्षी उपक्रम है। डिजिटल इंडिया के पीछे मूल दृष्टि है देश के हर नागरिक के लिए डिजिटल आधारभूत ढांचे तक पहुंच सुनिश्चित करना और इस ढांचे का उद्देश्य होगा एक माध्यम के रूप में नागरिकों तक विविध प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराना। नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार सरकारी सेवाओं और प्रशासन तक पहुंच प्राप्त कर सकें, यह इसका एक अन्य मकसद है। और ये तब संभव हो सकेगा जब नागरिकों को डिजिटल आधार पर सशक्त बनाया जाए।

अमेरिका के विश्व प्रसिद्ध मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन डिजिटल इंडिया पर केंद्रित होने वाला है। उधर वियतनाम ने डिजिटल इंडिया की तर्ज पर अपने यहां भी एक दीर्घकालीन कार्यक्रम शुरू करने की बात कही है। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने दावोस में कहा कि अमेरिका को डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कदमों का अनुसरण करना चाहिए।

ये घटनाएं और ये टिप्पणियां इस बात की निशानदेही करती हैं कि पिछले कुछ महीनों में 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम ने देश के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी लोगों को प्रेरित किया है। असल में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसे अनदेखा करना दुनिया के लिए असंभव है। मिसाल के तौर पर यह तथ्य कि आधार दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना के रूप में सामने आई है। एक अरब से ज्यादा लोगों को पुष्टि–योग्य डिजिटल पहचान प्रदान करना एक ऐसा लक्ष्य था जिसकी कामयाबी में शुरू से ही संदेह किया जा रहा था। लेकिन भारत ने यह कर दिखाया। और अब जिस तरह हम नकदी रहित अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं, वह विश्व के आर्थिक–प्रशासनिक इतिहास में एक और मिसाल कायम करने जा रहा है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की व्यापकता, प्रभाव, गहनता और नवीनता में लगातार वृद्धि होना प्रभावित करता है। हालांकि कार्यक्रम के क्रियान्वयन में बहुत–सी चुनौतियां और सीमाएं भी हैं जो भारत जैसे विविधतापूर्ण तथा आधारभूत सुविधाओं की दृष्टि से विकासमान देश के लिए स्वाभाविक हैं। लेकिन इस बात में कतई संदेह नहीं है कि डिजिटल इंडिया ने देश में डिजिटल सोच, डिजिटल नवोन्मेष, डिजिटल जागरूकता और डिजिटल महत्वाकांक्षा का माहौल बना दिया है। सरकारी विभागों में नए–नए डिजिटल कार्यक्रम शुरू करने की साफ होड़ दिखाई देती है तो राज्य सरकारें भी किसी से पीछे नहीं हैं।

खैर, सरकारें तो सरकारें हैं और उनके सामाजिक सरोकार एक अनिवार्यता हैं। लेकिन जिस बात से खासा संतोष होता है वह यह है कि निजी क्षेत्र और बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी डिजिटल इंडिया से जुड़कर गौरव का अनुभव कर रही हैं। वे इस कार्यक्रम की कामयाबी में अपनी तरफ से योगदान देना चाहती हैं। कुछ उदाहरण काबिले गौर हैं– माइक्रोसॉफ्ट ने इसी महीने जयपुर में एक कार्यक्रम में दस हजार रुपये से कम कीमत का लैपटॉप जारी किया, इस संकल्प के साथ कि ऐसे लैपटॉप डिजिटल क्रांति को गांव–गांव तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इस लैपटॉप में विंडोज का आधिकारिक (जेनुइन) संस्करण मौजूद है और तमाम वे सुविधाएं भी हैं जिनकी जरूरत सामान्य उपभोक्ता को पड़ती है। याद रहे, जब भारत में विमुद्रीकरण या नोटबंदी का ऐलान हुआ तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने विश्वास जताया था कि भारत तेजी से डिजिटल भुगतान की तकनीकों को अंगीकार कर लेगा।

इस बीच, गूगल ने डिजिटल भुगतान और डिजिटल कौशल में योगदान देने के लिए केंद्र सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के साथ मिलकर बड़ी योजना बनाई है। सिस्को ने साइबर सुरक्षा को चाकचौबंद करने के लिए करार किया है। ज्यों–ज्यों डिजिटल इंडिया का दायरा बढ़ेगा, साइबर चुनौतियां भी बढ़नी स्वाभाविक हैं। सैमसंग ने गांव–गांव तक डिजिटल स्मार्ट क्लास ले जाने की योजना शुरू की है। एचपी ने भारत में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरूआत की है। भारत की कंपनियां भी बड़े कदम उठा रही हैं और हजारों स्टार्टअप भी डिजिटल भारत के निर्माण की प्रक्रिया में हिस्सेदारी निभा रहे हैं। निजी क्षेत्र के प्रयासों में कारोबार की भी भूमिका अवश्य होगी लेकिन वह इस बारे में पर्याप्त लचीलापन दिखा रहा है, इसमें संदेह नहीं है।

अहम बात यह है कि निजी क्षेत्र में डिजिटल बदलाव (डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन) का जो दौर चल रहा है, वह उन्हें स्पष्ट रूप से लाभान्वित कर रहा है। यह लाभ सिर्फ आर्थिक हो, यह जरूरी नहीं। मिसाल के

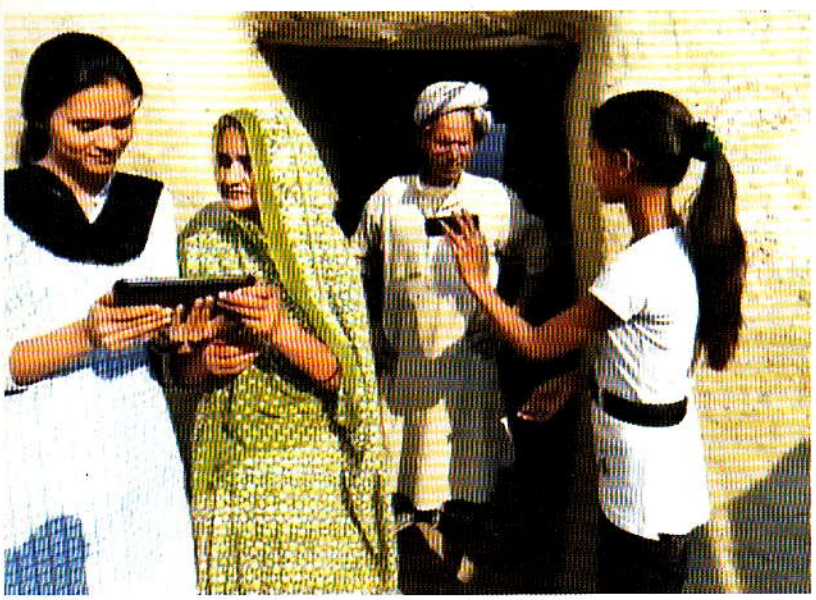

डिजिटल इंडिया: बढ़ते कदम

डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था और समाज में तब्दील करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में काफी काम हुआ है। कुछ ताजा उपलब्धियां काबिले गौर हैं–

विनिर्माण: भारत में विनिर्मित मोबाइल हैंडसेटों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और इनका आंकड़ा 2014 के 6 करोड़ से बढ़कर 2016–17 में 17.5 करोड़ मोबाइल सेटों तक पहुंच गया है। दो साल के भीतर लगभग 200 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। याद रहे, 2015–16 में यह आंकड़ा 11 करोड़ था। एलसीडी और एलईडी टेलीविजन सेटों के विनिर्माण में भी बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। जहां 2014–15 में देश में इस श्रेणी के 87 लाख टेलीविजन सेट विनिर्मित किए गए थे वहीं 2016–17 में उनकी संख्या 1.5 करोड़ इकाइयों तक पहुंच गई।

सरकारी खरीद: सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर होने वाली खरीददारी को लेकर तमाम किस्म की चिंताएं उठती रही हैं। केंद्र सरकार ने अब सरकारी खरीद के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल खोले जाने को मंजूरी दी है जिसका नाम सरकारी ई–बाजार या गवर्नमेंट ई–मार्केट प्लेस होगा। केंद्र और राज्य सरकारें यहां से सामान और सेवाओं की खरीद कर सकेंगी। इससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और प्रतिद्वंदी दरों पर सरकारी खरीद में मदद मिलेगी।

रेलवे की पहल: भारतीय रेलवे अपने पूरे सप्लाइ चेन सिस्टम का डिजिटल रूपांतरण करने जा रही है। सौ फीसदी ई–टेंडर और ई–बोलियां इसके तहत समाहित की जा चुकी हैं। इससे रेलवे की सामग्री, वित्त और सूचनाओं का सुगम प्रवाह सुनिश्चित करने के साथ–साथ पारदर्शिता तथा कारोबारी सुगमता को भी बढ़ावा मिलेगा। नई प्रणाली के तहत बिल पेश करने, जांच, डिस्पैच, प्राप्तियों, बिल पास करने की प्रक्रियाओं, भुगतानों, वारंटी की निगरानी और रेलवे की सप्लाई व्यवस्था को कार्यकुशल बनाने के लिए डाटा विश्लेषण क्षमताओं के व्यापक इस्तेमाल की योजना है।

सामान्य सेवा केंद्र: सरकारी सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए स्थापित किए गए सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। इन केंद्रों का प्रयोग अब कौशल विकास और आपूर्ति के माध्यम के रूप में भी किया जा रहा है। जहां सन 2014 में भारत में 80 हजार सामान्य सेवा केंद्र थे, वहीं 2015 में उनकी संख्या 1.5 लाख और 2016 में 2.1 लाख हो गई।

एकीकृत छात्रवृत्ति प्रणाली: छात्रवृत्तियां प्रदान करने की प्रक्रिया को न्यायसंगत, व्यापक और पारदर्शी बनाने के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल की उपयोगिता इस बात से सिद्ध हुई है कि अब इसमें 16 मंत्रालयों और विभागों की 23 छात्रवृत्ति योजनाएं पंजीकृत हो चुकी हैं। दो करोड़ से ज्यादा छात्रों ने यहां पंजीकरण कराया हुआ है। इसे तमाम छात्रवृत्तियों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया जा रहा है।

डिजिटल लेनदेन: विमुद्रीकरण के बाद जिस अंदाज में जनता ने डिजिटल लेनदेन को अपनाया है, वह डिजिटल इंडिया के लिए शुभ लक्षण कहा जा रहा है। नीति आयोग के अनुसार, मार्च 2017 में देश में 2,425 करोड़ रुपये के परिमाण के 63.80 लाख लेनदेन डिजिटल माध्यमों से हुए। इसकी तुलना अगर नवंबर 2016 से पहले के डिजिटल लेनदेनों से करेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि देश ने किस उत्साह से इन नए माध्यमों को अपनाया है। पिछले साल अप्रैल से लेकर नवंबर तक के आठ महीनों में 101 करोड़ रुपये के कुल लेनदेन इस माध्यम से

हुए थे, जिनकी संख्या थी 2 लाख 80 हजार। आधार के साथ जुड़े हुए लेनदेन का परिमाण भी नवंबर 2016 के बरक्स देखा जाए तो दो गुना बढ़ा है, यानी ढाई करोड़ लेनदेन की तुलना में पांच करोड़। त्वरित भुगतान सेवा (आईएमपीएस) के तहत हुए लेनदेन भी नवंबर 2017 के 3.6 करोड़ लेनदेन से बढ़कर मार्च 2017 में 6.7 करोड़ तक जा पहुंचे।

मौजूदा वित्तीय वर्ष में सरकार का 2500 करोड़ डिजिटल लेनदेनों का लक्ष्य है। इसमें मुश्किल नहीं आनी चाहिए, खासकर 75 शहरों को कम–नकदी–युक्त (लेस कैश) शहरों के रूप में आगे बढ़ाने की प्रधानमंत्री की घोषणा के मद्देनजर। प्रधानमंत्री के हाथों जारी किए गए भीम आधार एप्प को भी जनता ने हाथोंहाथ लिया है। आनन–फानन में ही इसे 27 प्रमुख बैंकों और 7.15 लाख कारोबारियों ने अपना लिया। इस बीच एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से होने वाले भुगतानों में भी जनवरी 2017 के 1660 करोड़ की तुलना में काफी बढ़ोतरी हुई है और दो महीने बाद, मार्च 2017 में वे 2000 करोड़ तक जा पहुंचे।

देश की मानसिकता में जो बदलाव आ रहा है, वह प्रधानमंत्री के इस कथन के अनुरूप ही है कि देश के विकास का नया मंत्र– जन–धन, जल धन और वन धन है। जन–धन योजना के तहत 30 करोड़ नए बैंक खातों का खुलना न सिर्फ आम आदमी को वित्तीय रूप से सशक्त करने वाला क्रांतिकारी कदम है बल्कि काफी हद तक सरकार से स्थानांतरित किए जाने वाले अनुदानों के सही व्यक्तियों तक पहुंचने की गारंटी भी देता है।

डिजिटल इंडिया के प्रभाव में जनता का मानस किस तरह बदल रहा है, उसका एक उदाहरण देखिए। एक मशहूर यात्रा पोर्टल की तरफ से कराए गए सर्वेक्षण से जाहिर हुआ है कि 90 फीसदी से ज्यादा भारतीयों ने अपनी छुट्टियों के लिए होटल, यात्रा आदि की बुकिंग करने में प्लास्टिक धन का इस्तेमाल किया। देश भर में तमाम डिजिटल परियोजनाओं ने विभिन्न सेवाओं को सुगम और पहुंच–योग्य बनाया है। राष्ट्रीय रोजगार पोर्टल के तहत दिव्यांगजनों के लिए अलग से एक रोजगार पोर्टल का काम जारी है। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से **महिला ई–हाट नामक ऑनलाइन प्लेटफार्म** का सफल संचालन हो रहा है। यहां ग्रामीण महिलाएं सीधे अपने उत्पादों की बिक्री कर पा रही हैं। अनेक राज्यों ने ग्रामीण भूमि नक्शा नवीसी और इन नक्शों के डिजिटलीकरण का काम शुरू किया है। कई राज्यों की सूचना प्रौद्योगिकी नीतियां जारी हुई हैं। डिजिटल मानसिकता, डिजिटल सोच और डिजिटल नवोन्मेष की ओर भारत की यात्रा निर्बाध जारी है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देशभर में ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को डिजिटल साक्षरता करने हेतु "प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान" को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के अनुमोदन के साथ, सरकार ने दुनिया में सबसे बड़े डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में से एक के लिए ₹ 2,351.38 करोड़ का बजट आवंटित किया है। सरकार को उम्मीद है कि यह परियोजना मार्च 2019 तक पूरी हो जाएगी। इस योजना के तहत वित्तवर्ष 2016–17 में 25 लाख, 2017–18 में 275 लाख और वित्तवर्ष 2018–19 में 300 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जाएगा। डिजिटल प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद, प्रत्येक व्यक्ति स्मार्टफोन और टैबलेट की तरह कंप्यूटर और अन्य डिजिटल उपकरणों को संचालित कर ई–मेल भेजने और इंटरनेट ब्राउज करने में सक्षम हो सकता है। इसका उपयोग सरकारी सेवाओं तक पहुंच हेतु, जानकारी के लिए खोज, और नकद रहित लेनदेन के कार्य में होगा। इस योजना के उचित कार्यान्वयन की जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और आईटी की निगरानी में राज्य और संघ–शासित प्रदेशों के सहयोग से निर्दिष्ट राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों और जिला ई–गवर्नेंस सोसायटी द्वारा की जाएगी। योजना का मुख्य उद्देश्य मोबाईल फोन के द्वारा नगद रहित लेन–देन के लिए डिजिटल वॉलेट, मोबाइल बैंकिंग, संयुक्त भुगतान इंटरफेस (यूपीआई), असंरचित पूरक डाटा सेवा (यूएसएसडी), और आधार सक्षम भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना है।

तौर पर हाल ही में एक सर्वेक्षण में कहा गया कि 55 प्रतिशत कंपनियां यह मानती हैं कि डिजिटल बदलाव से उनकी आय के नए स्रोत खुले हैं। चौरासी प्रतिशत कंपनियों ने कहा है कि इसकी बदौलत वे अपनी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों से बेहतर स्थिति में आ गई हैं। सत्तानवे प्रतिशत कंपनियों का मानना है कि उनके ग्राहकों को अब उनकी सेवाएं पहले से ज्यादा अच्छी महसूस हो रही हैं। यानी उनकी सेवाओं के प्रति ग्राहकों का अनुभव बेहतर हुआ है। पैंतीस प्रतिशत कंपनियां मानती हैं कि नए अवसरों का लाभ उठाने की उनकी क्षमता में इजाफा हुआ है। इतना ही नहीं, 56 प्रतिशत ने माना है कि नए बदलावों से उनके कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ी है। डिजिटलीकरण का व्यापक दौर हमारे इर्द–गिर्द घटित हो रहा है जिसके पीछे डिजिटल इंडिया की प्रेरणा या प्रभाव है।

डिजिटल इंडिया एक विशाल अभियान के रूप में आगे बढ़ रहा है। वह देश को डिजिटलीकृत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने का महत्वाकांक्षी उपक्रम है। डिजिटल लॉकर, ई–शिक्षा, ई–स्वास्थ्य, ई–हस्ताक्षर और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल जैसे कार्यक्रमों के साथ इसकी शुरूआत हुई। बहरहाल इस तरह के कार्यक्रम इसके पीछे की व्यापक दृष्टि के कुछ क्रियान्वयन मात्र हैं। डिजिटल इंडिया के पीछे मूल दृष्टि है देश के हर नागरिक के लिए डिजिटल आधारभूत ढांचे तक पहुंच सुनिश्चित करना और इस ढांचे का उद्देश्य होगा एक माध्यम के रूप में नागरिकों तक विविध प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराना। नागरिक अपनी आवश्यकता के अनुसार सरकारी सेवाओं और प्रशासन तक पहुंच प्राप्त कर सकें, यह इसका एक अन्य मकसद है। और ये दोनों चीजें तब संभव हो सकेंगी जब नागरिकों को डिजिटल आधार पर सशक्त बनाया जाए। ये तीनों बातें डिजिटल इंडिया के विज़न का हिस्सा हैं।

इस कार्यक्रम के नौ आधारभूत स्तंभों– ब्रॉडबैंड हाइवे, फोन की सुविधा तक सार्वत्रिक पहुंच, सार्वजनिक इंटरनेट पहुंच कार्यक्रम, ई–प्रशासन, ई–क्रांति (सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी), सबके लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स का विनिर्माण, रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और अर्ली–हारवेस्ट कार्यक्रम में से सभी में पिछले ढाई–पौने तीन साल के दौरान काफी प्रगति हुई है। डिजिटल इंडिया सन् 2019 तक देश के डिजिटल मानचित्र का कायाकल्प कर सकता है जो इन बिंदुओं से स्पष्ट है–

- ढाई लाख गांवों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा पहुंच चुकी होगी।
- सभी स्थानों पर फोन संपर्क की सुविधा सुनिश्चित हो जाएगी।
- 2020 तक सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार के क्षेत्र में उपकरणों के आयात पर निर्भरता न्यूनतम हो चुकी होगी।
- चार लाख सार्वजनिक इंटरनेट प्रयोग केंद्रों की स्थापना हो चुकी होगी।
- ढाई लाख विद्यालयों और सभी विश्वविद्यालयों में वाइ–फाइ इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्था हो चुकी होगी।
- बड़ी संख्या में नागरिकों के लिए वाइ–फाइ हॉटस्पॉट स्थापित हो चुके होंगे।
- सूचना प्रौद्योगिकी, दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्रों में 1.7 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित कर डिजिटल समावेशन के दायरे में लाया जा चुका होगा।
- इतने ही लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया जा चुका होगा और कम से कम 8.5 करोड़ लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मुहैया कराया जा चुका होगा।
- ई–प्रशासन और ई–सेवाओं को सभी सरकारों के स्तर पर व्यापक बनाया जा चुका होगा।
- स्वास्थ्य, शिक्षा और बैंकिंग जैसी सेवाओं के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग में भारत विश्व का अग्रणी देश बन चुका होगा।
- सार्वजनिक क्लाउड और इंटरनेट के प्रसार के जरिए नागरिकों को डिजिटल क्षेत्र में सशक्त बनाया जा चुका होगा।

जिन क्षेत्रों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, उनमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल भुगतान का क्षेत्र सबसे आगे दिखाई देता है। आधार के सूत्रधार नंदन निलेकणी ने हाल ही में कहा है कि भारत में तकनीकी प्रणालियां, भुगतान प्रक्रियाएं और आधारभूत ढांचा इतना सुदृढ़ है कि वह डिजिटल भुगतानों के मौजूदा स्तर के चार गुना तक को आसानी से वहन कर सकता है। एक अरब लोगों को डिजिटल माध्यमों से धन के लेन–देन की सुविधा देने में सक्षम ढांचा पहले ही हमारे पास मौजूद है। हालांकि पश्चिमी देशों में जहां डिजिटल अर्थव्यवस्था में कार्ड–आधारित लेन–देन की बहुतायत है वहीं भारत में अधिकांश डिजिटल लेन–देन मोबाइल फोन के माध्यम से होने हैं। **यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस एक जानदार परियोजना है जिसने बैंकों को आधार नंबर के माध्यम से धन का स्थानांतरण करने की शक्ति दे दी है। इतना ही नहीं, इसका प्रयोग करते हुए मोबाइल नंबर और पिन के माध्यम से भी धन का लेन–देन संभव हो गया है। इतने बड़े देश के पैमाने पर इस तरह की योजनाओं का सफलतापूर्वक लागू हो जाना किसी चमत्कार की बदौलत संभव नहीं हुआ है बल्कि सुसंगठित आधारभूत ढांचे, साइबर सुरक्षा के ठोस मॉडल और तकनीकी सक्षमता की बदौलत घटित हुआ है।** नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने अगर अमेरिका को भारत से सबक लेने की नसीहत दी है तो उसके पीछे इन कामयाबियों का बड़ा हाथ है।

(लेखक वरिष्ठ तकनीकविद् और स्तंभकार हैं।)
ई–मेल : balendu@gmail.com